



120

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना - 2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

Zone 'J'

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	MISHON KUMAR RAY
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्ल्यू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	INDIVIDUAL OFFICE OF THE DIR (Pig.) MPR/TC, D.D.A.N. DELHI-2 Dy.No. 2840 Dated 11/5/21
वर्तमान स्थिति Present Position	Ray Master Master of Hat
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9213266301
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	L-437A, Coli No. 15 Mahipalpur N.D. 37
हस्ताक्षर : Signature :	Ray
तिथि : Date :	8/5/2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं”

“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

88

767

भावी
दिल्ली - 2021

दक्षिणी जिले में आयोजित खुला मंच (ओपन हाउस मीट)
मे भाग लें और अपने सुझाव दें ।

स्थान: पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
आगस्त कांति मार्ग नई दिल्ली

तिथि: 08 मई 2012

सेवा में,

श्री ए. के. मन्ना, निदेशक योजना
दि० वि० प्रा० जोन (एफ एंड एच)
चौथा तल, विकास मीनार, नई दिल्ली

श्री चन्दू भूतिया, उपनिदेशक योजना
जोन जे०, 12वीं मंजिल,
विकास मीनार, नई दिल्ली

महोदय, उपरोक्त विषय पर टाटानगर नांगल डेरी से सभी विस्थापित करीब 100 परिवार
की ओर से सुझाव संग्रहक (पेज 18) है ।

प्रेषक

- 2 श्री एम के राय, के० आ० म० न० एल-437ए, गली नं० 15, महिपालपुर विस्तार, नई दिल्ली - 110037
- 3 श्री सुनील कुमार के० आ० म० नं० 112, डबल स्टोरी, विशाल एन्क्लेव, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली - 110027
- 4 श्री चन्द राजारिया के० आ० म० न० 232/के 2, ताराचन्द कालोनी, महिपालपुर विस्तार, नई दिल्ली - 110037
- 5 श्री अनिल कुमार बागड़ी के० आ० म० न० 539/ के 2 ताराचन्द कालोनी, महिपालपुर विस्तार, नई दिल्ली - 110037
- 6 श्री राधेश्याम के० आ० म० न० एल 43 / 327 महिपालपुर विस्तार, नई दिल्ली - 110037
- 7 श्री अनिल कुमार अटवाल के० आ० म० न० 10, गली नं० 16, रोड नं० 6, डी ब्लॉक, श्याम विहार, फेस 1, दीनपुर, नई दिल्ली - 1100043

8 मई 2012 को मास्टर प्लान संबंधी दक्षिण क्षेत्रीय बैठक में प्रेषित
मास्टर प्लान में पुनर्वास संबंधी स्पष्ट प्रावधानों का सुझाव

दिल्ली में प्रशासन ने समय समय पर पुनर्वास के उपयोग के लिए जमीन प्राप्त की थी। लेकिन मास्टर प्लान में पुनर्वास भू उपयोग कहीं नहीं दिखाया है और मास्टर प्लान बनाने बदलने के सिलसिले से वह जमीन अन्य उपयोगों में लगती जा रही है।

उदाहरणतयः जे जोन में करीब **147 एकड़** जमीन भूमी अर्जन अधिनियम की एमरजेन्सी धारा 17 तहत दिल्ली प्रशासन अधिमूचना No.F.7(2)/86-L&B dt.23 & 24/12/1986 द्वारा "सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् पालम हवाई अड्डे के विकास के कारण जो व्यक्ति प्रभावित होंगे या हटाए जाएंगे उनके पुनर्वास के लिए सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा प्राप्त" हुई थी। उस में से **63 एकड़** पुनर्वास में लगी और बाकी का उपयोग दिल्ली विकास अधिनियम की मास्टर प्लान संशोधन धारा 11 ए तहत अधिमूचनाओं से बदल लिया गया, जे बाद में 2008 के ड्राफ्ट जे जोन प्लान में शामिल थीं। पुनर्वास उपयोग के लिए प्राप्त बाकी की करीब **84 एकड़** भूमि का हिसाब 16/03/2009 को हुई केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक में दिल्ली प्रमुख सचिव से माँगा गया था, लेकिन जवाब नहीं आया। उक्त दिल्ली प्रशासन अधिमूचना व आयोग बैठक मिनट संलग्न हैं।

उल्लेखनीय है केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक दिल्ली प्रमुख सचिव के आदेश से 2006 में एयरपोर्ट क्षेत्र से टाटा नगर, नॉगल डेरी के जवरन विस्थापन के खिलाफ शिकायत के मामले में हुई थी। टाटा नगर निजी जमीन पर 1965 में बसाई पक्की कॉलोनी थी, जो बाद में एयरपोर्ट विस्तार में आ गई जिस के लिए भूमी अर्जन 1973 में शुरू हुआ। वहाँ वगैरे करीब 100 परिवारों को विस्थापन के समय निकट पुनर्वास का आश्वासन तब के डीडीए उपाध्यक्ष से प्राप्त था। इस संदर्भ में टाटा नगर परिवारों का जन शिकायत केस No.A-46017/108/09-PG DDA / MOUD में पेंडिंग है। उस केस में DDA सचिव के पत्र dt.25/08/10 अनुसार Director (MPD) को पत्र dt.04/09/2010 द्वारा पुनर्वास संबंधी सुझाव भेजे गए थे, जिसकी प्रति भी संलग्न है।

उपरोक्त संदर्भ में सुझाव है कि मास्टर प्लान में पुनर्वास संबंधी प्रावधान स्पष्ट करें ताकि टाटा नगर जैसे मामलों का संतोषजनक निपटान हो पाए।

टाटा नगर में विस्थापित करीब 100 परिवारों की ओर से

1. संपर्क पता: वी पी राजगिर्या, RZ-74 बजाज एन्क्लेव, काकरोला मोड़, Nr.NSIT, नई दिल्ली 110059

संलग्नः

दिल्ली प्रशासन अधिमूचना No.F.7(2)/86-L&B dt.23 & 24/12/1986	- 8 पेज
16/03/2009 को हुई केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बैठक के मिनट	- 1 पेज
जन शिकायत केस No.A-46017/108/09-PG में पत्र dt.04/09/2010	- 6 पेज

प्रिण्टिंग नं. डी. (जी. एन.)-187
REGISTERED NO. D (D.N.)-187

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

HC (दिल्ली प्रशासन)
HCC (दिल्ली प्रशासन)
DELHI ADMIN

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
असाधारण
EXTRAORDINARY

सं० 198] दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 1986/वोध 2, 1908
No. 198] DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 1986/PAUSA 2, 1908

PART IV भाग IV

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

भूमि व भवन विभाग
दिल्ली, 23 दिसम्बर 1986
अधिसूचनाएं

है, उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी
निर्देश देते हैं कि धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

विशिष्ट विवरण

क्रम सं.	गांव या इलाका	कुल क्षेत्रफल बीघा ब्रिस्वा	खसरा नं.	क्षेत्रफल बीघा ब्रिस्वा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	मालिक पुर	713	02 1740	3 16
	कोहो बनाम		1764	4 16
	रंगपुरी		1765	4 16
			1766	4 16
			1770/1	0 12
			1770/2	4 04
			1771	4 16
			1772	4 16
			1773	4 16
			1774	4 16
			1775	4 16
			1776	4 16
			1777	5 01
			1778	0 03

संख्या एफ. 7(2)/86-भू. व भ. : (1) जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् पालम हवाई अड्डे के विकास के कारण जो व्यक्ति प्रभावित होंगे या हटाए जाएंगे उनके पुनर्वास के लिये सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा भूमि प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिये भूमि का अपेक्षित किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिये प्रचलित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

उपराज्यपाल अपनी यह राय होने पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबन्ध इस भूमि पर लागू

301 DG 86

(1) Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication

1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
मालिक पुर	1779	4	13		मालिक पुर	1863	4	16	
बनाम रंगपुरी	1780	4	16		बनाम रंगपुरी	1864	4	16	
(जारी)	1781	4	16		(जारी)	1865	4	16	
	1782/1	3	12			1866	4	16	
	1782/2	1	04			1867	4	16	
	1783	4	16			1868	4	16	
	1784/1	3	08			1869	4	16	
	1784/2	1	12			1870	4	16	
	1785	7	08			1871	4	16	
	1786/1	2	04			1872	4	6	
	1786/2	2	12			1873	4	16	
	1787	4	16			1874	4	13	
	1788	4	16			1874	1	16	
	1789	4	16			1879	5	15	
	1790/1	2	18			1880	4	14	
	1790/2	1	18			1881 मित.	4	06	
	1791/1	0	17			1882	3	01	
	1791/2	4	03			1883	4	08	
	1836	4	16			1884	2	07	
	1837	4	16			1885	4	16	
	1838	4	16			1886	4	10	
	1839	4	16			1887	4	16	
	1840	4	16			1888/1	4	02	
	1841	4	16			1888/2	0	14	
	1842	4	16			1889	4	08	
	1843	4	16			1890	4	08	
	1844	4	16			1891	4	16	
	1845	4	16			1892/1	1	16	
	1846	4	16			1892/2	3	00	
	1847	4	16			1893/1	0	08	
	1848	4	16			1893/2	4	08	
	1849	4	16			1894/1	2	12	
	1850	4	16			1894/2	2	04	
	1851	4	16			1895/1	1	06	
	1852	4	16			1895/2	3	02	
	1853	4	16			1896	4	08	
	1854	4	16			1897	4	16	
	1855	4	16			1898	4	16	
	1856	4	16			1899	4	16	
	1857	4	16			1900	4	16	
	1858	4	16			1901	4	08	
	1859	4	16			1902	4	08	
	1860	4	16			1903	4	16	
	1861	4	16			1904	4	16	
	1862	4	16						

Asst. Controller (Business)

Gov. of India

Department of Publication

Civil Lines, Delhi-54

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
मालिक पुर		1905.	4	16	मालिक पुर		1968	4	16
बनाम रंगपुरी		1906	4	16	बनाम रंगपुरी		1969	4	16
(जारी)		1907	4	08	(जारी)		1970	4	16
		1908	4	08			1971	4	16
		1909	4	16			1972	4	16
		1910	4	16			1973	3	04
		1911	4	16			1974	7	04
		1912	4	16			1975	0	04
		1913	4	08			1976	4	12
		1938	1	12			1977	4	16
		1939	4	16			1978/1	3	04
		1940	4	16			1978/2	1	12
		1941	4	16			1979	4	16
		1942	4	16			1980	4	16
		1943	4	16			1981	4	16
		1944	4	16			1982/1	1	02
		1945/1	1	00			1982/2	3	14
		1945/2	3	16			1983	3	01
		1946/1	3	16			1984	6	07
		1946/2	1	00			1985	5	01
		1947/1	0	16			1986/1	3	07
		1947/2	4	00			1986/2	1	09
		1948/1	3	04			1987/1	4	01
		1948/2	1	12			1987/2	4	04
		1949	2	10			1987/3	0	12
		1950	3	10			1988/1	6	18
		1951	4	16			1988/2	4	18
		1952/1	1	04					
		1952/2	3	12					
		1953	4	16					
		1954	4	16					
		1955	4	16					
		1956	4	16					
		1957	4	16					
		1958/1	2	16					
		1958/2	2	00					
		1959	4	16					
		1960	4	16					
		1961	4	04					
		1962	4	02					
		1963	4	16					
		1964	4	16					
		1965	4	16					
		1966	4	16					
		1967	4	16					

LAND & BUILDING DEPARTMENT

Delhi, the 23rd December, 1986

NOTIFICATIONS

No. F. 7(2)/86-L & B. — Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that the land is likely to be required to be taken by the Government at the public expense for a public purpose, namely for rehabilitation of the persons displaced or effected due to the expansion/development of the Palam Airport. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be required for the above purpose.

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor is pleased to authorise the officers for the time being.

Asstt. Controller (Business)

Govt. of India

Department of Publication

1	2	3	4
Malikpur Kohi	1845	4	16
@ Rangpuri (contd)	1846	4	16
	1847	4	16
	1848	4	16
	1850	4	16
	1849	4	16
	1851	4	16
	1852	4	1
	1853	4	16
	1854	4	16
	1855	4	16
	1856	4	16
	1857	4	16
	1858	4	16
	1859	4	16
	1860	4	16
	1861	4	16
	1862	4	16
	1863	4	16
	1864	4	16
	1865	4	16
	1866	4	16
	1867	4	16
	1868	4	16
	1869	4	16
	1870	4	16
	1871	4	16
	1872	4	16
	1873	4	16
	1874	4	16
	1879	5	15
	1880	4	14
	1881 min.	4	06
	1882	3	01
	1883	4	08
	1884	2	07
	1885	4	16
	1886	4	10
	1887	4	16
	1888/1	4	02
	1888/2	0	14
	188	4	08
	1890	4	08
	1891	4	16
	1892/1	1	16
	1892/2	3	00
	1893/1	0	08
	1893/2	4	08
	1894/1	2	12
	1894/2	2	04
	1895/1	1	06

Malikpur Kohi	1895/2	3	02
@ Rangpuri (contd)	1896	4	08
	1897	4	16
	1898	4	16
	1899	4	16
	1900	4	16
	1901	4	08
	1902	4	08
	1903	4	16
	1904	4	16
	1905	4	16
	1906	4	16
	1907	4	08
	1908	4	08
	1909	4	16
	1910	4	16
	1911	4	16
	1912	4	16
	1913	4	08
	1938	1	12
	1939	4	16
	1940	4	16
	1941	4	16
	1942	4	16
	1943	4	16
	1944	4	16
	1945/1	1	00
	1945/2	3	16
	1946/1	3	16
	1946/2	1	00
	1947/1	0	16
	1947/2	4	00
	1948/1	3	04
	1948/2	1	12
	1949	2	10
	1950	3	10
	1951	4	16
	1952/1	1	04
	1952/2	3	12
	1953	4	16
	1954	4	16
	1955	4	16
	1856	4	16
	1957	4	16
	1958/1	2	16
	1958/2	2	00
	1959	4	16
	1960	4	16
	1961	4	04
	1962	4	02
	1963	4	16

1	2	3	4
Malikpur Kohi		1964	4 16
@ Rang erip (concl'd)		1965	4 16
		1966	4 16
		1967	4 16
		1968	4 16
		1969	4 16
		1970	4 16
		1971	4 16
		1972	4 16
		1973	04
		1974	7 04
		1975	0 04
		1976	4 12
		1977	4 16
		1978/1	3 04
		1978/2	1 12
		1979	4 16
		1980	4 16
		1981	4 16
		1982/1	1 02
		1982/2	3 14
		1983	3 01
		1984	6 07
		1985	5 01
		1986/1	3 07
		1986/2	1 09
		1987/1	4 01
		1987/2	4 04
		1987/3	0 12
		1988/1	6 18
		1988/2	4 18

संख्या एक 7(2)/86-भू. व. भ. (3)--भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलक्टर को सहव यह निर्देश देते हैं कि वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर ले जिसका विशिष्ट विवरण उनकी अधिसूचना संख्या एक 7(2)/86-भू. व. भ. (1) और (2) दिनांक 23-12-86 और 24-12-86 में दिया हुआ है।

आदेश से

एन. दिवाकर, सहाय सचिव
(भू. व. भ.)

No. F. 7(2)/86-L&B(3)--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Land Acquisition Act, the Lt. Governor of Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector, Delhi to take possession of land, the specification of which is given in his notification No. F.7(2)/86-L&B(1) and (2) dated 23-12-86 and 24-12-86 on the expiration of 15 days from the publication of the notification under sub-section (1) of section 9 of the said Act.

By Order,

N. DIWAKAR, Jt. Secy. (Land & Building)

Attest
Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in locality and do all other acts required or permitted by the section.

The Lt. Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to this land, is further pleased under sub-section 4 of the said section to direct that the provisions of section 5-A shall not apply.

SPECIFICATION

Name of village	Total Area Big.—Bis.	Khasra No.	Area Big.—Bis.
1	2	3	4
Malikpur Kohi	713 02	1740	3 16
@Rangpuri		1764	4 16
		1765	4 16
		1766	4 16
		1770/1	0 12
		1770/2	4 04
		1771	4 16
		1772	4 16
		1773	4 16
		1774	4 16
		1775	4 16
		1776	4 16
		1777	5 01
		1778	0 03
		1779	4 13
		1780	4 16
		1781	4 16
		1782/1	3 12
		1782/2	1 04
		1783	4 16
		1784/1	3 08
		1784/2	1 12
		1785	7 08
		1786/1	2 04
		1786/2	2 12
		1787	4 16
		1788	4 16
		1789	4 16
		1790/1	2 18
		1790/2	1 18
		1791/1	0 17
		1791/2	4 03
		1836	4 16
		1837	4 16
		1838	4 16
		1839	4 16

1	2	3	4
Malikpur Kohi		1840	4 16
@Rangpuri		1841	4 16
(contd).		1842	4 16
		1843	4 16
		1844	4 16
		1845	4 16
		1846	4 16
		1847	4 16
		1847	4 16
		1850	4 16
		1849	4 16
		1851	4 16
		1852	4 16
		1853	4 16
		1854	4 16
		1855	4 16
		1856	4 16
		1857	4 16
		1858	4 16
		1859	4 16
		1860	4 16
		1861	4 16
		1862	4 16
		1863	4 16
		1864	4 16
		1865	4 16
		1866	4 16
		1867	4 16
		1868	4 16
		1869	4 16
		1870	4 16
		1871	4 16
		1872	4 16
		1873	4 16
		1874	4 16
		1879	5 15
		1880	4 14
		1881min.	4 06
		1882	3 01
		1883	4 08
		1884	2 07
		1885	4 16
		1886	4 10
		1887	4 16
		1888/1	4 02
		1888/2	0 14
		1889	4 08
		1890	4 08
		1891	4 16
		1892/1	1 16
		1892/2	3 00

Asst. Controller (Business)

Govt of India

Department of Publication

1	2	3	4
Malikpur Kohi		1845	4 16
@ Rangpuri (contd)		1846	4 16
		1847	4 16
		1848	4 16
		1850	4 16
		1849	4 16
		1851	4 16
		1852	4 1
		1853	4 16
		1854	4 16
		1855	4 16
		1856	4 16
		1857	4 16
		1858	4 16
		1859	4 16
		1860	4 16
		1861	4 16
		1862	4 16
		1863	4 16
		1864	4 16
		1865	4 16
		1866	4 16
		1867	4 16
		1868	4 16
		1869	4 16
		1870	4 16
		1871	4 16
		1872	4 16
		1873	4 16
		1874	4 16
		1879	5 15
		1880	4 14
		1881 min.	4 06
		1882	3 01
		1883	4 08
		1884	2 07
		1885	4 16
		1886	4 10
		1887	4 16
		1888/1	4 02
		1888/2	0 14
		188	4 08
		1890	4 08
		1891	4 16
		1892/1	1 16
		1892/2	3 00
		1893/1	0 08
		1893/2	4 08
		1894/1	2 12
		1894/2	2 04
		1895/1	1 06

1	2	3	4
Malikpur Kohi		1895/2	3 02
@ Rangpuri (contd)		1896	4 08
		1897	4 16
		1898	4 16
		1899	4 16
		1900	4 16
		1901	4 08
		1902	4 08
		1903	4 16
		1904	4 16
		1905	4 16
		1906	4 16
		1907	4 08
		1908	4 08
		1909	4 16
		1910	4 16
		1911	4 16
		1912	4 16
		1913	4 08
		1938	1 12
		1939	4 16
		1940	4 16
		1941	4 16
		1942	4 16
		1943	4 16
		1944	4 16
		1945/1	1 00
		1945/2	3 16
		1946/1	3 16
		1946/2	1 00
		1947/1	0 16
		1947/2	4 00
		1948/1	3 04
		1948/2	1 12
		1949	2 10
		1950	3 10
		1951	4 16
		1952/1	1 04
		1952/2	3 12
		1953	4 16
		1954	4 16
		1955	4 16
		1856	4 16
		1957	4 16
		1958/1	2 16
		1958/2	2 00
		1959	4 16
		1960	4 16
		1961	4 04
		1962	4 02
		1963	4 16

1	2	3	4	5
मलिकपुरकोही		1965	4	16
बनाग		1966	4	16
रंगपुरी (जासी)		1967	4	16
		1968	4	16
		1969	4	16
		1970	4	16
		1971	4	16
		1972	4	16
		1973	3	04
		1974	7	04
		1975	0	04
		1976	4	12
		1977	4	16
		1978/1	3	04
		1978/2	1	12
		1979	4	16
		1980	4	16
		1981	4	16
		1981/1	1	02
		1982/2	3	14
		1983	3	01
		1984	6	07
		1985	5	01
		1986/1	3	07
		1986/2	1	09
		1987/1	4	01
		1987/2	4	04
		1987/3	0	12
		1982/1	6	18
		1988/2	4	18

Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

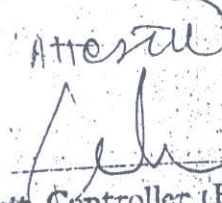
A plan of the land may be inspected at the Office of the Collector of Delhi.

SPECIFICATION

Name of Village	Total Area Bigha-Biswas	Khasra No.	Area Bigha-Biswas
1	2	3	4
Malikpur Kohi & Rangpuri	713 02	1740	3 16
		1764	4 16
		1766	4 16
		1770/1	0 12
		1770/2	4 04
		1771	4 16
		1772	4 16
		1773	4 16
		1774	4 16
		1775	4 16
		1765	4 16
		1776	4 16
		1777	5 01
		1778	0 03
		1779	4 13
		1780	4 16
		1781	4 16
		1782/1	3 12
		1782/2	1 04
		1783	4 16
		1784/1	3 08
		1784/2	1 12
		1785	7 08
		1786/1	2 04
		1786/2	2 12
		1787	4 16
		1788	4 16
		1789	4 16
		1790/1	2 18
		1790/2	1 18
		1791/1	0 17
		1791/2	4 03
		1836	4 16
		1837	4 16
		1838	4 16
		1839	4 16
		1840	4 16
		1841	4 16
		1842	4 16
		1843	4 16
		1844	4 16

No. F.7(2)/86-L&B:—(2) Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that the land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, namely, for "Rehabilitation of the persons displaced or effected due to the expansion/development of the Palam Air Port". It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, to all whom it may concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the Collector of

Attest

 Assistant Controller (Business)
 Govt. of India
 Department of Publication

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25/2	1-04	25/1	1-04					16-10
		51/11/1	3-04	51/11/1	3-04					
		51/19	4-12	51/12	4-12					
		51/20	4-12	51/20	4-12					
		255	2-02	255	2-02					
		14/1/2	1-01	14/1/2	1-01					
		14/1/3	1-17	14/1/3	1-17					
		14/2	2-02	14/2	2-02					
		14/4	1-7	14/4	1-07					
		14/6	5-10	14/6	5-10					
		14/7	4-12	14/7	4-12					
		14/8	4-16	14/8	4-16					
		14/9	4-16	14/9	4-16					
		14/10	4-16	14/10	4-16					
		14/11	4-16	14/11	4-16					
		14/12	4-16	14/12	4-16					
		40/5/1	2-12	40/5/1	2-12					
		50/26	9-18	50/26	5-18					
		13/5/1	4-7	13/5/1	4-7					
		13/5/2	0-2	13/5/2	0-2					
		13/3/2	3-09							
		13/4	4-16							
		13/7	3-10	13/7 min	0-03					
		13/8/1	3-08							
		13/13/1	0-19							
		13/12/2	0-11							
		Total:	129-07		112-17					
	Grand Total :		329-16	313-06						6-10
1. Irrigated by Govt source of one crop yielding			54-16	53-06						1 10
2. Irrigated by Govt source of two crop yielding			32-05	17-05						15-0
3. Irrigated by Pvt. source of one crop yielding			19-06	19-06						
4. Irrigated by Pvt. source of two crop Yielding			157-15	157-15						
5. Unirrigated			65-14	65-14						
Total :			329-16	133-06						16-10 equal to 60 bighas of (c) cat.

B.S. RANA, COMPETENT AUTHORITY : DELHI.

Attested
[Signature]
 Asstt Controller (Business)
 Govt. of India
 Department of Publication
 Civil Lines, Delhi-54

10


**MINUTES OF THE MEETING HELD ON 16.3.2009 BY HON'BLE CHAIRMAN, NCSC,
DR. BUTA SINGH ON DEMOLITION OF TATA NAGAR, NANGAL DAIRY**

The Senior officials of Ministry of Civil Aviation, MCD, NCT of Delhi and DIAL, who appeared before the Hon'ble Chairman Dr. Buta Singh on 16.3.2009 at 12.00 Noon to discuss the matter relating to eviction/dislocation and demolished of the Scheduled Castes families residences of Tata Nagar, Nangal Dairy.

Hon'ble Chairman pointed out to the authorities that as per the petitioners the Scheduled Castes inhabiting the areas were original owners. The Nangal Dairy area was not a slum/JJ area. The Chairman further pointed out that the very orders of eviction/demolition were not correct and desired to know as to who gave such orders. He desired to have a copy of the orders of eviction of 1973 and asked ADM Shri Rajshekar to send a copy of the same.

Hon'ble chairman also decided to know from Chief Secretary of govt. of NCT Delhi, if there was any court case on the subject and outcome of the case with copies of order. The report may be obtained from Chief Secretary on the points decided above within 20 days. Apart from above, it was also decided to obtain information about the land (84 acres) acquired in Malikpur Cohn for rehabilitation of displaced persons for Delhi gazette dated 23/24 December, 1986.

The meeting ended with vote of thanks to the Chair.


(BUTA SINGH) 26/3/09
Chairman, NCSC

1/

04/09/10

To: Sh P.V.Mahashabdey, Director(MPD), DDA,
6th Floor Vikas Minar, New Delhi 110002
Sub: PG Case No.A-46017/108/09-PG Submission of suggestion
Ref: DDA Commissioner Cum Secretary's letter dt 25/08/2010
Sir,

We are petitioners in above PG case. Copy of the letter under reference is *enclosed*. In terms of its para 3b we submit the *enclosed* suggestion. Copies are also *enclosed* of letter dt.12/08/10 to which the letter under reference replies and the further letter dt.03/09/10 to the Commissioner cum Secretary.


2. As indicated in the letter dt.03/09/10 we do not know if we may address you. From what we have understood, our PG case was sent to you and your office sent it to zonal units. However, we do not want to miss any opportunity.

3. As may be seen in para E of our suggestion, our requests already made to Ministry are regarding plot / site planning. From what we have understood, that is jurisdiction of zonal planning units. We have elaborated only the one general request regarding plan modifications that in our understanding may concern your office because the Public Notices are of Master Plan Section.

Yours faithfully,


Shanti Devi


Likhi Ram


Ram Kishan


Radheshyam

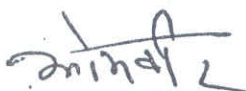

B P Rajoria


Data Ram

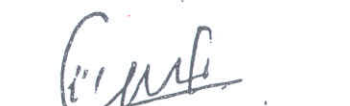
Sunil


Satpal


Ramesh Kumar


Om Vir Rajoria


Shrichand Rajoria


Mehar Chand Bhagwana

RSVP: Om Vir Rajoria,
231 Mahipalpur Extn, Tarachand Colony, Nr Neelkanth Mandir, N.Delhi 110037

Encl. 1. Letter dt.25/08/10 of Commissioner cum Secretary (1 page)
2. Suggestion (2 pages)
3. Letters dt.12/08/10 & 03/09/10 (2 pages)

Copy for kind information to:

1. Commissioner Cum Secretary, DDA, Vikas Sadan, N.Delhi 110023
2. Sh C.K.Basu, Under Secretary (C&PG), MOUD -PG Cell, N.Delhi 110011

डी. सरकार

मायुक्त एवं सचिव

D. SARKAR

COMMISSIONER-CUM-SECRETARY



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
विकास सदन, आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023
Vikas Sadan I.N.A., New Delhi-110023

Ph. : 24623598

Fax : 24692962

25th August 2010

Di. _____

F3 (368)/2010/DPR/DDA/RTI/ 219

SH. B.P. RAJORIA
RZ-74, BAJAJ ENCLAVE EXTN.,
KAKROLA MORH, NEAR NSIT,
NEW DELHI-110 059.

Sub: Application dated 12-8-2010

Please refer to your above mentioned application addressed to the undersigned.

Reply to the request made by you at para 3 of your application is as under:-

Para 3 a. With reference to your RTI application ID No. 6073 dated 24-12-09, available information with DDA has already been provided to you by the PIO vide letter No. F:7(02)2010/RTI/PB-I(Min.)/DDA/344 dated 09-2-2010 on which you had also filed your first appeal with Commissioner (Personnel)/Appellate Authority. If you were not satisfied with the reply of the Appellate Authority in response to your first appeal, you should have filed a Second Appeal with the CIC within the stipulated period under the RTI Act. Further reference of your RTI application to the PIO is not considered necessary as your first appeal has already been disposed of.

Para 3 b. With regard to your joint grievance petition received from MoUD, the same was forwarded by Dy. Dir. (PG) to Dir. (MPD). vide letter No. F84(92)2009/P.G./DDA dated 03-9-2009 for disposal. As the matter pertains to rehabilitation of displaced persons due to expansion of airport, you may seek further clarification from/or submit your suggestion to the Director (MPD) being Appellate Authority in the case as the same is not under the jurisdiction of the undersigned.


(D. Sarkar)
Commissioner-cum-Secretary

Master / Zonal Plan 2021 modifications under Section 11A of DD Act
Suggestion of approx.100 SC families earlier inhabiting Tata Nagar

Our approx.100 SC families were among those who agreed to Government's request to shift homes from vicinity of Palam Airport for its safety in 1965 war. Our families established, in arrangement with private rural land owner, tenant colony with pucca homes named Tata Nagar. At time of acquisition of that land for airport expansion in 1973, then DDA Vice Chairman assured alternative accommodation in vicinity. We understand "vicinity" would mean at most rest of the zone 'G' having airport area in south part and surrounding zones 'F','J' & 'K-II'. Zonal plans thereof are finalised since June 2010. By letter dt.12/08/10 to Jt.Secretary(D&L) we have requested that in *all* plan modifications the plot first be checked for suitability for us. This is because:

- A. In December 2006 we were displaced without rehabilitation. We are suffering hardship as a result of DDA's failure to meet the assurance given to us in writing in 1973. We believe we are entitled to priority in terms of its special care duty under Article 46 of the Constitution.
- B. In 1986 141 acres in zone 'J' was urgently acquired invoking section 17 of Land Acquisition Act to rehabilitate persons to be displaced for airport expansion. But only 63 acres was used for a scheme only for Nangal Dewat village. Use of rest was changed bit by bit by modifying the Master Plan. After the displacement also use of 30 acres was changed for Defence purpose of officers' housing, without considering objections in response to Public Notice of 2007 for that. We are aggrieved by misuse of section 11A of DD Act to change the rehabilitation use fixed under Land Acquisition Act. We are entitled to redress via section 11A.
- C. Before our displacement in December, in August 2006 DDA had invited objections/suggestions on a draft 'J' zone plan showing as 'Residential' the left over rehabilitation land (including the 30 acres later changed for Defence purpose of officers' housing). Our suggestion was to show detail and we had requested urgent hearing. Hearing was not given till 2008 and then, while Board found our suggestion to compensate rehabilitation land in 'J' zone plan fair, 'J' zone planning Director decided not to. We are aggrieved by this wilfulness. Because we did not choose the 'J' zone site or Director, we are entitled to consideration in the entire "vicinity".
- D. In 2008 objections/suggestions were invited also on draft 'G' zone plan. We had suggested detailing of residential use in south part of zone 'G' and also of the part of Airport expansion area given to M/s DIAL for profitable use. Due to short notice we missed hearing opportunity. Final plan incorporates request of not yet displaced village Shahbad to be rehabilitated within airport area. We believe if we had got proper notice for hearing on 'G' zone plan in 2008 similar decision could have come also for us. We are aggrieved by carelessness in zonal plan process and so special care duty is especially owed to us in further planning process.

14

hearing. Board recommended that proposal but Ministry did not finalize it. Separately DMRC indicated it could not rehabilitate at that station and we clarified to the Ministry we are not picking sites and are only requesting that a site for our rehabilitation in the "vicinity" be decided before finalizing DMRC proposals and plans of zones 'G' & 'J'. This request and our complaint against 'J' zone plan were filed as grievances with Ministry in 2009. They are batched as case No.A-46017/108/09-PG titled "P.G. case regarding rehabilitation of SC Persons displaced for Airport Expansion", in which reply of DDA Director(PG) is pending since 27/08/09. Till Ministry's Reminder-3 dt.15/07/10 named Smt.Neemo Dhar, we could not even know who DDA Director(PG) is and only by June did we learn our case, forwarded on 03/09/10 by PG office to Master Plan office was pending since 13/03/10 in 'G' & 'J' zone units under same Director. Meanwhile, plans of zones 'G' & 'J', and 'F' & 'K-II', were finalized by notices of June 2010. One of us, vide letter dt.12/08/10 to Jt.Secretary(D&L), requested the Ministry to now ensure that:

- "a) Till our PG case is resolved:
- i) DDA G zone planning unit does not finalize its Madipur proposal in which our hearing is not completed; and
 - ii) DDA Planning wing, in each proposal to change land use of any plot in vicinity of displacement area (i.e in zones G, F, J and K-II), first checks if the use proposed is more worthy of that plot than fulfillment of DDA VC's assurance of 1973 to us and the proposed user is more owed than us the state's duty of special care under Article 46 of the Constitution. This suggestion is already submitted for the plot in Dwarka for which the hearing was held on 09/08/10.
- b) For resolving our PG case, with zonal plans already finalized, now:
- i) DDA considers modifying G zone plan to add provision for our rehabilitation within DIAL area, like it has done for Shahbad Muhamadpur while finalizing G zone plan; or
 - ii) DDA finds ways to make DMRC rehabilitate us, as was duly suggested by us for the reason that MRTS station has come up on site of our displacement; or
 - iii) DDA prioritizes our rehabilitation in the LIG component of its under construction 56 Ha J zone scheme between Vasant Kunj and the site acquired but not used for rehabilitation purpose. This scheme was justified with reference to approval of the rehabilitation site, for contiguity. In the land use change for it in 2002-03, Board had recommended and Technical Committee and Authority had approved that zonal plan would ensure the EWS/LIG housing that is very short of Master Plan requirement in the existing contiguous schemes. Cause of our grievance is, as stated, that G&J zone planning Director is in habit of ignoring such decisions.
- c) DDA's undue delay in PG case of displaced SC citizens is not indulged like all its other acts of indifference to our hardship for four years."

The request vide para (a)(ii) above is the suggestion herein.

- F. We are seeking to suggest a possible way for the priority that we believe is owed by the DDA, in terms of its special care duty under Article 46 of the Constitution of India, to our approx. 100 SC families whom the DDA has neglected and failed in planning process since 1973, in public process for zonal plans in 2006-08, and in PG process since 2009.

15

R&D CELL 151/C-C-Scary
VIRGIL DAN 43-2-12
Dy. No.
Date. 12/08/2010

From: B.P.RAJORIA

RZ-74, Bajaj Encl Extn, Kakrola Morh, Near NSIT, ND 110059

To: Sh D.Sarkar, Commissioner Cum-Secretary, DDA

Sub: RTI case ID 6073 dt.24/12/09 and PG Case No.A-46017/108/09-PG

Sir,

RTI case ID 6073 is of my only RTI request to DDA, for information about DDA Chairman. Smt Neemo Dhar, Director (PR) & PIO, had decided / suggested to Director (Personnel) to transfer to LG Secretariat. LG Sectt PIO rejected. As no other Appellate Authority [AA] was named, I filed appeal with LG Sectt AA who upheld PIO's decision that DDA has to provide the information. Meanwhile, I had made jointly with others a representation dt.23/03/10 to Hon'ble VC for favour of marking our RTI cases to correct DDA PIOs. In response we had received Smt Neemo Dhar's letter dt.19/04/10 informing AA for each case, Commissioner (Personnel) for mine. Accordingly, after LG Sectt AA's rejection, I filed appeal dt.11/05/10 with Commissioner (Personnel). Copy is enclosed (11 pages). I received no decision.

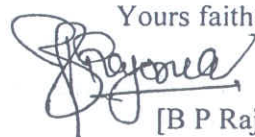
2. PG Case No.A-46017/108/09-PG is "P.G. case regarding rehabilitation of SC Persons displaced for Airport Expansion". I am one of the petitioners, named at no.7 in MOUD letter dt.27/08/08 whereby it was forwarded to DDA Director (PG) to reply to each petitioner within 15 days. Copies of MOUD letter dt.27/08/10 and latest Reminder-3 dt.15/07/10 are enclosed (3 pages). Director(PG) has not replied and it is not known / clear who Director(PG) is because:

- a) Reminder-3 names Smt Neemo Dhar. However, Smt Neemo Dhar's response dt.19/04/10 to our joint letter to VC, in which name of Director(PG) was also requested, had not named herself or anyone.
- b) Same representation of Sh Data Ram to MOUD w.r.t which Reminder-3 is copied to him was submitted by myself to DDA Board of Enquiry & Hearing to request presence of Director(PG) at its hearing on 05/07/10. Planning officers present had informed there is no separate Director(PG) and they only act as Director(PG) for the PG cases concerning Planning, whereupon the Board asked them to fix hearing to decide this PG case and intimate the petitioners within a week. However, they did not intimate.
- c) No one has replied even after MOUD Reminder-3 dt.15/07/10

3. What is clear is that Smt Neemo Dhar's letter dt.19/04/10 did not resolve even the minor matter of correctly/clearly identifying PIO/AA and Director(PG), resulting in undue inconvenience and denial of information in RTI case and continuing hardship and denial of redress in PG case. Since DDA Director(PG) is still not known / clear, I request your favour for:

- a. Marking my RTI case ID 6073 dt.24/12/09 to correct PIO/AA; and
- b. Reference of my PG case back to MOUD Director of Grievances for redress.

Yours faithfully,


[B P Rajoria]

Enclosed: As above, 14 pages

784